भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

<u>दिसम्बर, 2021 के लिए मासिक सारांश</u>

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. माह के दौरान, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार (रु. 741.8 करोड़), ओडिशा (रु. 333.80) करोड़), तमिलनाडु (533.20 करोड़ रुपये), त्रिपुरा (28.20 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (1441.60 करोड़) राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए मूल (अबद्ध) अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालयने वित्त वर्ष 2020-21 के लिएमेघालय राज्य को 45.50 करोड़ रुपये के मूल अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है। अब तक, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में 25406.50 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों/पारंपरिक स्थानीय निकायों के लिए पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और घरेलू अपशिष्ट, मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधनआदि के प्रबंधन और उपचार सहित ओडीएफ स्थिति के रखरखाव के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए जारी की गयी है।

2. पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्रालय से छत्तीसगढ़ (215.00 करोड़ रुपये), केरल (240.60 करोड़ रुपये) मध्य प्रदेश (588.80 करोड़ रुपये), सिक्किम (6.20 करोड़) और उत्तराखंड (82.48 करोड़ रुपये) राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग मूल (अबद्ध) अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश की है।

3. स्वामित्व योजना के तहत, गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले गांव के गृह मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है और अन्य राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए चर्चा चल रही है। दिनांक 28 दिसंबर, 2021 को असम सरकार, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, दिनांक 23 दिसंबर,2021 कोमाननीय प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को स्वामित्वयोजना के तहत संपत्ति दस्तावेजों "घरौनी" को डिजिटल रूप से वितरित किया। साथ ही, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर परउत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया में हैं जहां संपत्ति कार्ड संतोषजनक ढंग से वितरित किए जाते हैं। अब तक 94,000 गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी कर ली गयी है और 88 जिलों के समस्त गांवों में ड्रोन-सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है।

4. पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध वित्त के प्रबंधन के लिएपंचायती राज मंत्रालय राज्यों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए सख्ती से प्रयासरत है। इस संबंध में, मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए राज्यों से अनुरोध कर रहा है। चालू वर्ष यानी वर्ष 2021-22 में 83% ग्राम पंचायतों ने अपनी मंथ बुक बंद कर दी हैं।

5. 2,31,500 पंचायती राज संस्थाएं ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) पर ऑनबोर्ड हो चुकी हैं। दिसंबर माह 2021 में 1,86,653 पंचायती राज संस्थाओं ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के व्यय के लिए ईजीएसपीआई का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन किया है।

6. इसके अलावा, पीआरआई स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करते हुएपंचायती राज मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज में रसीद प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए 'पीएफएमएस के साथ राज्य ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन' की प्रक्रिया में है। 23 राज्यों ने स्टेट ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन की इस कवायद को पूरा कर लिया है।

7. साथ ही, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिएमंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत एक एप्लिकेशन - ऑडिटऑनलाइन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है और आंतरिक और वाहय ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। वर्ष 2019-20 के लिए, 27 राज्यों (केरल सहित) ने पहले ही 7,680 ऑडिटर, 2,47,333 ऑडिटी को पंजीकृत कर लिया है और 14वें वित्त आयोग के खातों की ऑडिट के लिए 1,27,083 ग्राम पंचायतों की ऑडिट योजनाएं तैयार की हैं। इस एप्लिकेशन पर राज्यों द्वारा 10,78,280 टिप्पणियां दर्ज की गई हैं और 27 राज्यों ने ऑडिट रिपोर्ट (98,620 रिपोर्ट) तैयार की हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 1,14,928 ग्राम पंचायतों, 1,292 ब्लॉक पंचायतों और 57 जिला पंचायतों द्वारा ऑडिट योजनाएं तैयार की गई हैं। राज्यों द्वारा 6,78,119 टिप्पणियां दर्ज की गई हैं और कुल 46,486 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं, जिनमें से 45,694 ग्राम पंचायतों द्वारा, 761 ब्लॉक पंचायतों द्वारा और 31 जिला पंचायतों द्वारा तैयार की गई हैं।

8. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना के तहत मिजोरम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और नागालैंड राज्यों की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद में 75.926 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

9. 7 दिसंबर, 2021 कोमाननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, श्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से 'सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण' पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण की प्रभावी निगरानी के लिए जीपीडीपी और प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) की प्रगति की निगरानी के लिए पंचायत विकास योजना निगरानी डैशबोर्ड का भी शुभारम्भ किया।

10. पीपीसी 2021 के तहत पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन 13 और 14 दिसंबर, 2021 को त्रिपुरा में पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर के लिए किया गया था। इस कार्यशाला में इन राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

11. पंचायती राज संस्थानों में एसडीजी के स्थानीयकरण पर यूनिसेफ इंडिया के साथ 22 दिसंबर, 2021 को एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सक्रिय सहयोग के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण पर काम को आगे बढ़ाने के लिए बुलाई गई थी। पीआरआई में एसजीडी को स्थानीयकृत करने के लिए रिपोर्ट में 9 विषयों की पहचान की गई है। जिसमें थीम 3 - चाइल्ड फ्रेंडली विलेज जहां यूनिसेफ ने (i) भारत भर में पंचायती राज संस्थानोंमें चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायतों को चाइल्ड राइट्स को साकार करके और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर एजेंडा 2030 प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (ii) जमीनी स्तर पर बच्चों और महिलाओं के लिए एसडीजी में परिकल्पित लक्ष्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए दीर्घकालिक स्थायी समाधानों का संस्थानीकरण करने में बहुत काम किया है।

12. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) के लिए पंचायती राज संस्थानों के सभी तीन स्तरों के लिए ऑनलाइन नामांकन 31 दिसंबर, 2021 तक राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों से चार श्रेणियों, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत आमंत्रित किए गए थे। इन पुरस्कारों के लिए पंचायतों से 51,620 से अधिक (ग्राम पंचायत-49,783, ब्लॉक पंचायत-1531 और जिला पंचायत-306) आवेदन प्राप्त हुए हैं।

13. आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) श्रृंखला में छठा, 20 दिसंबर 2021 को 'आत्मनिर्भर पंचायत - सतत विकास के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और ऊर्जा दोहन की भूमिका' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया था। सचिव, पंचायती राज ने मुख्य भाषण दिया और राष्ट्रीय वेबिनार में पंचायती राज मंत्रालय, आमंत्रित मंत्रालयों / विभागों, आईआईटी-दिल्ली, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, राज्यों के पंचायती राज विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी एवं पीआर) और पंचायती राज संस्थानों के बहुत बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारी वीसी लिंक

के साथ-साथ एनआईसी वेबकास्ट लिंक के माध्यम से दूर से राष्ट्रीय वेबिनार में शामिल हुए। राष्ट्रीय वेबिनार में उन्नत भारत अभियान के केंद्रों से भी लोग शामिल हुए। पंचायती राज मंत्रालय भी दिनांक 13.12.2021 से 19.12.2021 के सप्ताह के दौरान रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह के उत्सव में शामिल हुआ, जिसमें (i) दो मिनट का मौन रखना, (ii) 1971 के युद्ध के दौरान शहीदों और सैनिकों की वीरता और बलिदान पर भारतीय शहीदों को सम्मानित करने जैसी गतिविधियों पर चर्चा की गई और (iii) सप्ताह के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इंडिया गेट, नई दिल्ली के पास हाल ही में खोले गए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा करना। इसके अलावा, मंत्रालय ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों से इस उत्सव में भाग लेने का आहवान किया। मंत्रालय ने डीएआरपीजी के तत्वावधान में सुशासन सप्ताह भी मनाया क्योंकि मंत्रालय ने विशेष अभियान के माध्यम से लंबित जन शिकायतों पर ध्यान देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक परामर्श जारी किया था। मंत्रालय ने तत्काल प्राप्त जन शिकायतों के अलावा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी लक्षित सार्वजनिक शिकायतों के 100% निपटान में भी भाग लिया।

14. 1 दिसंबर, 2021 को मंत्रालय के पास 118 शिकायतें/याचिकाएं लंबित थीं और दिसंबर माह के दौरान 477 (अर्थात 444 ऑनलाइन + 33 भौतिक) शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। कुल 595 (दिसंबर में प्राप्त 477 + पिछले महीने से 118 अग्रेषित) में से, 515 शिकायतों / याचिकाओं का दिसंबर में निपटारा किया गया और 80 को 1 जनवरी, 2022 तक आगे बढ़ाया गया।

15. दिसंबर 2021 के दौरान, ई-ऑफिस सिस्टम में 133 ई-फाइलें खोली गईं, जो इस माह के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of December, 2021

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realize the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram SwarajAbhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. During the month, the Ministry of Finance (MoF) has released 2nd installment of Basic (Untied) Grants for FY 2021-22 for Rural Local Bodies for the States of Bihar, (Rs. 741.8 Crores), Odisha (Rs.333.80 Crore), Tamil Nadu (Rs.533.20 Crore), Tripura (Rs. 28.20 Crore) and Uttar Pradesh (1441.60 crore). Further, MoF has released 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 45.50 crore for FY 2020-21 to the State of Meghalaya. As on date, XV FC grants to the tune of Rs. 25406.50 crore for F.Y. 2021-22 has been released by the Ministry of Finance to the States for Rural Local Bodies/Traditional Local Bodies for improving basic services including supply of drinking water, rain water harvesting, water recycling, sanitation & maintenance of ODF status including management and treatment of household waste, human excreta and faecal sludge management, etc.

2. The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has recommended to MoF for release of 2nd installment of XV FC Basic (Untied) Grants for FY 2021-22 for the States of Chhattisgarh (Rs. 215.00 Crores), Kerala (Rs.240.60 Crore), Madhya Pradesh (Rs.588.80 Crore), Sikkim (6.20 Crore) and Uttarakhand (Rs. 82.48 Crore).

3. Under the SVAMITVA Scheme, with the aim to provide the 'Record of Rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of Property cards to the Property owners, 29 States/UTs have signed a memorandum of understanding with the Survey of India for the implementation of Scheme and discussions are on-going with other States for signing of MoU.

Tripartite MoU among Govt. of Assam, Bodoland Territorial Council and Survey of India signed on 28-Dec-21. Further, on 23rd Dec 2021, Hon'ble PM digitally distributed property documents "Gharauni" under SVAMITVA Scheme to over 20 Lakh residents of Uttar Pradesh. Also, on the occasion of birth anniversary of former Prime Minister of India, Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee, Property cards were distributed in State of Uttarakhand, Haryana, Karnataka and UT of Ladakh. States/ UTs are in process of passing GP Resolution in the Gram Panchayats where property cards are distributed satisfactory. Till now, drone flying has been completed in 94,000 villages and drone-survey completed in all villages of 88 districts.

4. For management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. In the current year i.e. 2021-22, 83% GPs have closed their month books.

5. 2,31,500 PRIs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI). In the month of December 2021- 1,86,653 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred XV Finance Commission Grant.

6. Further, strengthening the accountability and transparency at the PRI level; MoPR is in the process of 'Reverse Integration of State Treasury system with PFMS' to capture the receipt entries automatically in eGramSwaraj. 23 States have completed this exercise of reverse integration of State treasury system.

7. Also, for strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For the year 2019-20, 27 States (including Kerala) have already registered 7,680 Auditors, 2,47,333 Auditees and prepared Audit Plans of 1,27,083 GPs for Auditing 14th Finance Commission accounts. 10,78,280 observations have been recorded by States on the application and 27 States have generated audit reports (98,620 Reports). For the year 2020-21, audit plans have been prepared by 1,14,928 GPs, 1,292 BPs and 57 ZPs. 6,78,119 observations have been recorded by States and total 46,486 audit reports have been generated out of which 45,694 by GPs, 761 by BPs and 31 by ZPs generated.

8. Funds to the tune of Rs.75.926 Cr has been released under the scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) towards the approved AAP of the states of Mizoram Maharashtra, Andhra Pradesh and Nagaland.

9. On 7th December 2021, Hon'ble Union Minister of Rural Development and Panchayati Raj, Shri Giriraj Singh released the Expert Group Report on the 'Localization of Sustainable Development Goals (SDGs)' through Panchayati Raj Institutions. He also launched Panchayat Development Plan Monitoring Dashboard for monitoring the progress of GPDPs and Training Management Portal (TMP) for effective monitoring of trainings for Capacity Building and Training of Elected Representatives and Functionaries of Panchayati Raj Institutions.

10. Two-Days Regional Workshop on Economic & Social Transformation through Panchayat Development Plans under PPC 2021 was organized on 13th and 14th December, 2021 at Tripura for NE States of Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Sikkim and Manipur. Senior Officers and Elected Representatives of these States participated in the workshop.

11. A Meeting was held on 22ndDecember, 2021 with UNICEF India on Localising SDGs in PRIs. This meeting was called for to take forward the work on localization of SDGs through active collaboration. The 9 themes have been identified in the report to localize the SGDs in PRIs. In which Theme 3 – Child Friendly Village where UNICEF has done immense work in (i) Localization of Sustainable Development Goals to achieve Agenda 2030 by realizing Child Rights and promotion of Child Friendly Gram Panchayats in PRIs across India. (ii) To institutionalization of long-term sustainable solutions to help achieve the goals and targets envisaged in the SDGs for children and women at the grassroots.

12. For National Panchayat Awards 2022 (Appraisal year 2020-21) online nominations for all three tiers of Panchayati Raj Institutions were invited by 31stDecember, 2021 from State Governments/Union Territory (UT) Administrations under the four categories namely, DeenDayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar, Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar, Gram Panchayat Development Plan Award and Child-friendly Gram Panchayat Award. More than 51,620 applications have been received from Panchayats (Gram Panchayat-49,783, Block Panchayat-1531 and District Panchayat-306) for these awards.

13. Sixth in the Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM) Series, a day-long National Webinar with the theme 'Atmanirbhar Panchayats – Role of Technology, Entrepreneurship and Harnessing Energy in Achieving Self-reliance for Sustainable Development' was organized on 20 December 2021. The Secretary, PR delivered key note address and the National Webinar was attended by all senior officers of the Ministry of Panchayati Raj, invitee Ministries/ Departments, IIT–Delhi, Office of the Principal Scientific Adviser to GoI, Department of Panchayati Raj of States and Union Territories, State Institute of Rural Development & Panchayati Raj (SIRD&PRs) and a large number of elected representatives and functionaries of Panchayati Raj Institutions joined the National Webinar remotely through VC link as well as NIC Webcast link. People joined the National Webinar from centres of Unnat Bharat Abhiyan as well. The Ministry of Panchayati Raj also joined the celebration of the iconic week of the Ministry of Defence during the week 13.12.2021 to 19.12.2021 with activities like honouring the Indian martyrs by (i) observing two minutes silence, (ii) discussing on the valour and sacrifices of the martyrs and soldiers during 1971 war and also (iii) visiting to recently opened National War Memorial near India Gate, New Delhi by the officials of the Ministry during the week. In addition, the Ministry, through respective States/UTs, called upon the Panchayati Raj Institutions to take part in this celebration. The Ministry also, observed Good governance week under the aegis of DARPG as the Ministry issued necessary advisory to the States/UTs to attend to pending public grievances through special drive. The Ministry too attended

100% disposal of all targeted public grievances received from various sources, besides the instantly received public grievances.

14. There were 118 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st December, 2021 and 477 (i.e. 444 online + 33 physical) grievances/ petitions were received during the month of December. Out of total 595 (477 received in December + 118 carried forward from last month), 515 grievances/petitions were disposed in December and 80 were carried forward as on 1stJanuary, 2022.

15. During December 2021,133 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****